

सक्षिप्त समाचार

सबसे अच्छा कचरा अलग करने वालों को मिलेगा इनाम

चेन्नई। ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (जीसीसी) से शहर के दक्षिणी क्षेत्र में अपना 40 दिन का घरेलू कचरा अलगाव जागरूकता अभियान फिर से शुरू करेगा। अधिकारियों ने बताया कि जिन घरों को ‘कलेक्शन बैग’ मिले हैं, वहां लोगों की भागीदारी में सुधार देखा गया है। इस पहल का नाम ‘कचरे को अलग करें-कल को बचाएं’ रखा गया है। इसे 22 अगस्त को शुरू किया गया था, लेकिन लक्षित घरों में सूखे कचरे के बैग और मॉनिटरिंग रिटर्न के वितरण को पूरा करने के लिए इसे रोक दिया गया था। कार्यक्रम के लिए पहचाने गए 50,000 घरों में से 45,000 घरों तक सामग्री पहुंच चुकी है। अधिकारियों ने कहा कि बाकी वितरण जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद औपचारिक रूप से 40 दिन का चैलेंज शुरू होगा। अभियान के अंत में सबसे अच्छी तरह से कचरा अलग करने वाले परिवारों को पुरस्कार दिया जाएगा।

दिल्ली में अब बिना पीयूसी नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

नई दिल्ली। दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण बढ़ने से पहले सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए नए कदम लागू किए हैं। इसके तहत ‘नो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, नो फ्यूल’ नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है। अब वैध पीयूसी (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल पंप पर वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। इस नियम को लागू करने के लिए दिल्ली के करीब 500 पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक सिस्टम लगाया गया है। इन पेट्रोल पंपों पर कैमरे लगाए गए हैं, जो परिवहन विभाग के डेटाबेस से जुड़े हैं। सिस्टम वाहन का नंबर स्कैन कर यह पता करता है कि उसका सर्टिफिकेट वैध है या नहीं। बिना वैध ष्ट्र वाली गाड़ी के पेट्रोल पंप पर पहुंचते ही सिस्टम उसका नंबर पहचान लेता है। इसके बाद ऑटोमैटिक अनाइसमेंट के जरिए वाहन मालिक को बताया जाता है कि गाड़ी के पास वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं है। ऐसे वाहन को तत्काल ईंधन देने से रोक दिया जाता है।

मंदिर परिसर में 2 सेवादारों के शव मिलने से हड़कंप

शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के खुदागंज थाना क्षेत्र के सूथा गांव में प्राचीन मंदिर परिसर में दो सेवादारों के जले हुए शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों की हत्या के बाद शवों को जलाए जाने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिर परिसर में पहुंच गए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। मृतकों की पहचान मंदिर के सेवादार गोपाल दास और बाबा बिहारी दास के रूप में हुई है। ग्रामीणों के मुताबिक, दोनों मंदिर परिसर में ही रहते थे और धार्मिक कार्यों में सेवा करते थे। सुबह ग्रामीण मंदिर पहुंचे तो परिसर में दोनों के शव पड़े मिले।

भारतीय महिला हॉकी टीम का ऐतिहासिक कारनामा-44 साल का इंतजार खत्म

भारत ने रचा इतिहास-चीन को 1-0 से हराकर जीता हॉकी गोल्ड

नई दिल्ली/ एजेंसी

एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। जापान के नागोया में खेले गए गोल्ड मेडल मुकाबले में भारत ने दुनिया की नंबर-4 टीम और मौजूदा एशियन चैंपियन चीन को 1-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लालरेम्सियामी ने 10वें मिनट में दागा गोल पूरे मुकाबले का निर्णायक गोल साबित हुआ। भारतीय डिफेंस और गोलकीपर सविता पूनिया ने इसके बाद चीन के लगातार हमलों को रोकते हुए बढ़त को अंत तक कायम रखा। इस जीत के साथ भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन गेम्स गोल्ड का 44 साल पुराना इंतजार खत्म कर दिया। भारत ने इससे पहले 1982 में नई दिल्ली में महिला हॉकी का स्वर्ण पदक जीता

था। यह एशियन गेम्स में भारत का दूसरा महिला हॉकी गोल्ड मेडल है। भारत ने 1998 और 2018 में सिल्वर, जबकि 1986, 2006, 2014 और 2023 में ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं। भारत की इस ऐतिहासिक जीत का असर सिर्फ एशियन गेम्स तक सीमित नहीं है। गोल्ड मेडल जीतने के साथ भारत ने लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया है। लंबे इंतजार के बाद मिला यह स्वर्ण पदक भारतीय महिला हॉकी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बन गया है। दुर्भाग्य से भारत की ओर से दीपिका 21 गोल के साथ टॉप स्कोरर रहीं। उनके बाद भारतीय टीम की नवनीत कौर ने 10 गोल किए, जबकि चीन की जियाकी झोंग 9 गोल के साथ सूची में तीसरे स्थान पर रहीं। फइनल में हालांकि भारत के लिए लालरेम्सियामी का



गोल ही निर्णायक रहा और टीम ने पूरे मुकाबले में अपनी बढ़त बचाए रखी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मैच की शुरुआत से ही चीन पर अपना दबदबा बनाए रखा। हालांकि, खेल के छठे मिनट सूची में तीसरे स्थान पर रहीं। फइनल में हालांकि भारत के लिए लालरेम्सियामी का

के 10वें मिनट में लालरेमसियामी ने एक शानदार फिड गोल करके भारत को 1-0 से बढ़त दिला दी। यह लालरेमसियामी का 200वां इंटरनेशनल मैच था। इसके बाद भारत को गोल करने का एक और मौका (पेनल्टी कॉर्नर) मिला, लेकिन टीम उसे गोल में बदलने से चूक गई।

अचानक कंडक्टर बन गए सीएम विजय

खुद काटने लगे टिकट महिलाओं के लिए फ्री

नई दिल्ली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने शुक्रवार को राज्य भर में महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा का विस्तार करते हुए वेट्टी प्यनम तोट्टम योजना के नए चरण का शुभारंभ किया। इसके तहत अब और भी कई श्रेणियों को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। गांधी जयंती के अवसर पर इस योजना की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री विजय ने चेन्नई में खुद बस से यात्रा की। इस दौरान उन्होंने खुद मुफ्त टिकट भी काटे। बस में सफर कर रही कालेज छात्राओं ने मुख्यमंत्री को टिकट के बदले चांकलेट दिए। इस योजना



से प्रतिदिन लगभग 84.32 लाख महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। लाभार्थी राज्य परिवहन निगमों द्वारा संचालित 12,695 बसों में मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। इसमें एक्सप्रेस और डीलक्स श्रेणी की सेवाएं भी शामिल की गई हैं।

कैप्टन रश्मि मच्छर ने सुनाई खौफनाक आपबीती

संकट में पड़ा हनुमान चालीसा मोदी बोले-आप पर गर्व है.....

नई दिल्ली/ एजेंसी

फ्लाईडुबई की दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट सी1073 में बुधवार को हुए गंभीर कॉकपिट हमले के बाद भारतीय पायलट कैप्टन रश्मि मच्छर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वीडियो कॉल पर पूरी घटना का अनुभव साझा किया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद रश्मि ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने में सफलता हासिल की, जिसके बाद यात्रियों और कर्ू ने हमलावर को काबू करने में मदद की। विमान में 174 लोग सवार थे और बाद में इसे सऊदी अरब के



तबुक में सुरक्षित उतारा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कैप्टन रश्मि मच्छर से वीडियो कॉल पर बातचीत की और संकट के दौरान उनके साहस, सूझबूझ और संयम की सराहना की। बातचीत के दौरान रश्मि भावुक हो गईं। उन्होंने

प्रधानमंत्री से कहा कि उनसे बात करना उनके लिए बेहद खास और गर्व का क्षण है। उन्होंने मोदी को अपना बड़ा आदर्श बताया। कैप्टन रश्मि ने मोदी को बताया कि मुश्किल समय में वह हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। घटना के दौरान भी वह लगातार हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। उन्होंने बताया कि हमले के बाद वह घायल होकर गिर गए थे, लेकिन उन्हें पता था कि विमान में क्या हो रहा है और उनके पास कार्रवाई करने के लिए बहुत कम समय था। इसके बाद उन्होंने खुद को संभाला और कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया।

मेट्रो स्टेशन पर थूकदान देख भड़के लोग, 500 रुपए जुर्माने के बीच लगाथूकदान

मुंबई। मुंबई मेट्रो के एक स्टेशन पर लगाए गए अनोखेथूकदान 'की तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद भारी बहस छिड़ गई है। मेट्रो परिसर में जहां पान-गुटखा खाकर गंदगी फैलाने और थूकने पर सख्त पाबंदी के साथ 500 के जुर्माने का नियम लागू है, वहीं इस तरह के थूकदान लगाए जाने से यात्री और आम नागरिक हैरान हैं। लोग मेट्रो प्रशासन के इस कदम पर सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ थूकने पर आर्थिक दंड का प्रावधान है, तो दूसरी तरफ ऐसा इंतजाम करके क्या प्रशासन इस अव्यांछित आदत को बढ़ावा दे रहा है।

मोहन भागवत का बड़ा बयान: धर्म और राष्ट्र अलग नहीं

धर्म संकट में आया तो देश भुगतेगा खामियाजा-मोहन

नई दिल्ली/ एजेंसी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को कहा कि भारत में धर्म और राष्ट्र को अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता। मुंबई में ऑल इंडिया विहार सेवा रूफ के 14वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्र का उद्देश्य धर्म है और धर्म राष्ट्र को बनाए रखने में मदद करता है। उन्होंने कहा कि दोनों एक-दूसरे पर निर्भर हैं और धर्म संकट में आने पर देश को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मोहन भागवत ने कहा कि भारत ने कभी दूसरे देशों पर



संदिग्ध गतिविधियों को भांपते हुए त्वरित कार्रवाई की। पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में अवैध रूप से दाखिल होने का प्रयास कर रहे दो घुसपैठियों को जवानों द्वारा रोका गया। चेतावनी के बावजूद जब वे नहीं माने, तब सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों घुसपैठियों को ढेर कर दिया।

विरोध प्रदर्शनों के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

एसआईआर के बाद छूटे नामों की होगी पहचान-ईसी घर-घर जाकर जोड़ेगा नाम

नई दिल्ली/ एजेंसी

देश में एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को लेकर बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर चुके राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में छूटे हुए पात्र मतदाताओं और पहली बार वोट देने वाले युवाओं के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इसके तहत बृथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और पात्र लोगों को फॉर्म-6 के जरिए मतदाता सूची में शामिल कराने में मदद करेंगे। आयोग के 1 अक्टूबर 2026 के निर्देश के मुताबिक, बीएलओ प्री-एसआईआर मतदाता सूची और मौजूदा

मतदाता सूची की तुलना करेंगे। इस दौरान ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी, जिनका नाम पहले की मतदाता सूची में था, लेकिन वर्तमान सूची में नहीं है। इसके अलावा पहली बार मतदान के पात्र हुए युवाओं और अन्य पात्र नागरिकों को भी इस विशेष अभियान में शामिल किया जाएगा। चुनाव आयोग के निर्देश में कहा गया है कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान बीएलओ ने अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरे मतदाताओं की सूची तैयार की थी। अब विशेष अभियान के दौरान मौजूदा मतदाता सूची की तुलना प्री-एसआईआर सूची से की जाएगी। इससे ऐसे मतदाताओं की पहचान की जाएगी: जिनका नाम प्री-एसआईआर सूची में था, लेकिन वर्तमान सूची में नहीं है। जो एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में शामिल नहीं हो



पाए। जो पहली बार मतदान के पात्र हुए हैं। ऐसे युवा और अन्य पात्र नागरिक जिनका नाम अभी मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। आयोग ने कहा है कि विशेष अभियान का उद्देश्य ऐसे पात्र मतदाताओं की पहचान कर उन्हें नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराना है। इस अभियान

की सबसे महत्वपूर्ण बात घर-घर जाकर सत्यापन है। बीएलओ संबंधित मतदाताओं के घर जाकर उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी लेंगे। यदि व्यक्ति अभियान का उद्देश्य ऐसे पात्र मतदाताओं की पहचान कर उन्हें नामांकन के लिए फॉर्म-6 के माध्यम से आवेदन कराने में

सहायता की जाएगी। आयोग ने बीएलओ को प्रति सप्ताह करीब 20 से 25 मतदाताओं को कवर करने का लक्ष्य दिया है। पूरी कवायद को लगभग एक महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बीएलओ विशेष अभियान के दौरान तैयार की गई सूची में प्रत्येक संबंधित मतदाता की वर्तमान स्थिति दर्ज करेंगे। जिन मतदाताओं के लिए फॉर्म-6 भर दिया जाएगा, उनके नाम के सामने इसकी जानकारी भी दर्ज की जाएगी। इसके बाद सूची को भरे गए फॉर्म-6 और मैदानी सत्यापन रिपोर्ट के साथ संबंधित चुनाव पंजीकरण अधिकारी यानी ईआरओ को सौंपा जाएगा। अंतिम कार्रवाई ईआरओ द्वारा संबंधित कानून और नियमों के तहत की जाएगी। चुनाव आयोग ने विशेष अभियान में राजनीतिक दलों की भागीदारी का भी प्रावधान रखा है।

जंतर-मंतर पर एसआईआर के खिलाफप्रदर्शन, सौरभ भारद्वाज समेत कई नेता हिरासत में

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के कामकाज के तरीकों को लेकर राजनीतिक पारा पूरी तरह चढ़ गया है। विभिन्न विपक्षी दलों, वामपंथी संगठनों और छात्र युनियनों ने शुक्रवार को चुनाव आयोग के खिलाफजंतर-मंतर पर एक विशाल विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। इस विरोध प्रदर्शन को लेकर बढ़ते राजनीतिक तनाव और संभावित कानून-व्यवस्था की स्थिति को भांपते हुए दिल्ली प्रशासन और पुलिस पहले से ही पूरी तरह मुस्तेद नजर आई। जंतर-मंतर और इसके आसपास के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई।

संपादकीय

राष्ट्रों की सुरक्षा संबंधी चिंताएं, ऐतिहासिक विवाद और क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मगर यह भी उतना ही सच है कि युद्ध जितना लंबा खिंचता है, उसके आर्थिक दुष्परिणाम भी उतने ही व्यापक होते जाते हैं।रूस वह देश है, जहां लियो टाल्स्टायन ने ‘युद्ध और शांति’ की रचना के जरिए मनुष्य की हिंसक प्रवृत्ति और शांति की आकांक्षा को उजागर किया था। आज उसी धरती पर युद्ध जैसे

समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चौथे वर्ष से आगे निकल चुका है और मध्य-पूर्व में अमेरिका तथा ईरान के बीच महीनों से जारी संघर्ष ने वैश्विक अस्थिरता को और गहरा कर दिया है।सवाल केवल यह नहीं कि युद्ध कब खत्म होंगे, बल्कि यह है कि आधुनिक दुनिया में शांति की राह लगातार इतनी कठिन क्यों होती जा रही है। सितंबर में रूस के संसदीय चुनाव के अंतिम दिन यूक्रेन ने वहां बड़े

पैमाने पर ड्रोन हमले किए। रूस का दावा है कि इस दौरान डेढ़ हजार से अधिक ड्रोन मार गिराए गए। हमलों में कुछ लोगों की मौत हुई और एक प्रमुख तेल प्रतिष्ठान को भी नुकसान पहुंचा।यह हमला ऐसे समय हुआ, जब रूस में 18 से 20 सितंबर तक स्टेट ड्यूमा के चुनाव हो रहे थे। रूस की सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल किया और 450 सदस्यीय ड्यूमा में 355 सीटें जीतने का एलान

जटिल संघर्षों से उपजी वैश्विक अस्थिरता

किया। इन चुनावों को क्रेमलिन ने युद्ध के बीच अपने शासन और नीतियों के लिए समर्थन के संकेत के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि आलोचकों और कुछ पर्यवेक्षकों ने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। यहां चुनाव और युद्ध का यह संयोग एक असहज प्रश्न खड़ा करता है कि क्या लंबे समय से चल रहे युद्धों में राजनीति और सैन्य रणनीति एक-दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ जाती हैं कि शांति की संभावना लगातार पीछे

खिसकती जाती है? इसका उत्तर किसी एक देश या नेता के व्यवहार में नहीं, बल्कि उस अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में तलाशना होगा, जहां सुरक्षा, सत्ता, संसाधन और रणनीतिक हित एक-दूसरे में उलझ चुके हैं। मध्य-पूर्व की स्थिति इस जटिलता को और बढ़ाती है।अमेरिका और ईरान के बीच लंबे संघर्ष ने होर्मुज जलमार्ग को वैश्विक चिंता का केंद्र बना दिया है। यह दुनिया के महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है। इसके आसपास तनाव

बढ़ने का असर केवल युद्धरत पक्षों पर ही नहीं पड़ता, बल्कि तेल, गैस, जहाजरानी, बीमा और आपूर्ति-व्यवस्था के जरिए उसका प्रभाव दूर-दूर तक पहुंचता है। अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थों के जरिए बातचीत भी हुई, लेकिन युद्ध समाप्त करने और होर्मुज से आवागमन सामान्य बनाने पर अभी पूर्ण सहमति नहीं बन सकी है। युद्धों की आधुनिक त्रासदी यह है कि उनके लक्ष्य अक्सर सीमाओं से आगे निकल जाते हैं।

पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा प्रश्न आतंकवाद को लेकर उसकी नीति का है। भारत लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि पाकिस्तान की धरती से या उसके संरक्षण में सक्रिय आतंकी नेटवर्क भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती पैदा करते हैं। जयशंकर ने इसी संदर्भ में कहा कि आतंकवाद और मित्रता साथ- साथ नहीं चल सकते और आतंकवाद के कर्ता को अपना रास्ता बदलना होगा। दूसरी ओर पाकिस्तान भारत पर भी आतंकवाद को समर्थन देने के आरोप लगाता है और अपने यहां होने वाली हिंसक घटनाओं के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराता है।

(ललित गर्ग)

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 26 सितंबर को महासभा में सटीक, तीक्ष्ण एवं प्रभावी वक्तव्य में पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि एक 'सीरियल प्रैक्विशनर ऑफ टेररिज्म' ने एक दिन पहले तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया और आतंकवाद को सामान्य बनाने तथा उसके परिणामों से बचने का प्रयास किया, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें अधिवेशन में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर वही पुराने सवाल सामने आए, जिनका समाधान दक्षिण एशिया की शांति और स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 81वां अधिवेशन 8 सितंबर 2026 से शुरू हुआ और इसकी सामान्य बहस 22 से 26 सितंबर के बीच हुई। इस वर्ष की बहस का घोषित केंद्रीय विषय था- विश्वास बहाल करना, परिवर्तन का प्रबंधन करना और ऐसी संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था बनाना जो सभी के लिए प्रभावी हो। ऐसे समय में जब दुनिया युद्धों, आतंकवाद, आर्थिक असमानता, ऊर्जा संकट और भू-राजनीतिक तनाव से जूझ रही है, यह सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है कि दक्षिण एशिया कब पुराने विवादों के चक्र से बाहर निकलेगा।

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 26 सितंबर को महासभा में सटीक, तीक्ष्ण एवं प्रभावी वक्तव्य में पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि एक 'सीरियल प्रैक्विशनर ऑफ टेररिज्म' ने एक दिन पहले तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया और आतंकवाद को सामान्य बनाने तथा उसके परिणामों से बचने का प्रयास किया, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध आत्मरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग करेगा और आतंकवाद को प्रायोजित करने वाली सरकारों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। उन्होंने आतंकवाद के वित्तीय स्रोतों को उजागर करने और उन पर कार्रवाई की आवश्यकता भी रेखांकित किया। इसके एक दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने संबोधन में कश्मीर का प्रयोग किया, जबकि भारत की ओर से पाकिस्तान के सीमा-पार आतंकवाद संबंधी रुख पर सवाल उठाए गए। पाकिस्तान की प्रतिनिधि ने भी भारत पर आतंकवाद और कश्मीर को लेकर गंभीर आरोप लगाए। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र का मंच एक बार फिर दोनों देशों के पारस्परिक आरोप-प्रत्यारोप का साक्षी बना। लेकिन असली प्रश्न यह है कि इन आरोपों के बाद भी समाधान की दिशा में कितना रास्ता तय हुआ?

पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा प्रश्न आतंकवाद को लेकर उसकी नीति का है। भारत लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि पाकिस्तान की धरती से या उसके संरक्षण में सक्रिय



आतंकी नेटवर्क भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती पैदा करते हैं। जयशंकर ने इसी संदर्भ में कहा कि आतंकवाद और मित्रता साथ-साथ नहीं चल सकते और आतंकवाद के कर्ता को अपना रास्ता बदलना होगा। दूसरी ओर पाकिस्तान भारत पर भी आतंकवाद को समर्थन देने के आरोप लगाता है और अपने यहां होने वाली हिंसक घटनाओं के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराता है। इन परस्पर आरोपों की सच्चाई और प्रमाण अलग-अलग मामलों में जांच का विषय हो सकते हैं, लेकिन इतना निर्विवाद है कि पाक आतंकवाद को पोषित कर भारत की शांति का भंग करता रहा है, इन आतंकी घटनाओं ने दोनों देशों की जनता को भारी मानवीय, आर्थिक और सामाजिक कीमत चुकाने पर मजबूर किया है। तो फिर सवाल उठता है-पाकिस्तान आखिर कब यह स्वीकार करेगा कि आतंकवाद किसी भी राष्ट्र की स्थायी विदेश नीति नहीं बन सकता? आतंकवाद यदि किसी देश के लिए रणनीतिक साधन बनता है तो अंततः वही साधन उस देश की आंतरिक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता के लिए भी समस्या बन सकता है। पाकिस्तान स्वयं लंबे समय से आतंकवादी हिंसा से जूझ रहा है। ऐसे में उसके सामने यह ऐतिहासिक अवसर है कि वह आतंकवाद के प्रश्न को केवल भारत-विरोधी दृष्टिकोण से न देखकर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और भविष्य के संदर्भ में भी देखे। आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई केवल किसी दूसरे देश की मांग पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है।

दूसरा प्रश्न कश्मीर का है। पाकिस्तान ने इस बार भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का मुद्दा उठाया। लेकिन लगभग आठ दशक से चली आ रही इस बहस ने यह साबित कर दिया है कि

केवल अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बयान देने से समस्या का समाधान नहीं होता। कश्मीर के नाम पर भारत और पाकिस्तान के बीच अविश्वास बढ़ता है, सुरक्षा तनाव पैदा होता है और दोनों देशों की विकास प्राथमिकताएं प्रभावित होती हैं। यदि पाकिस्तान वास्तव में क्षेत्रीय शांति और स्थिरता चाहता है, तो उसे यह विचार करना होगा कि कश्मीर को अपनी विदेश नीति के स्थायी केंद्र में रखकर वह अपने नागरिकों के भविष्य के लिए क्या हासिल कर रहा है। हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का उल्लेख करना और घरेलू समस्याओं को पीछे छोड़ देना किसी भी देश के लिए दीर्घकालिक समाधान नहीं हो सकता। तीसरा और शायद सबसे गंभीर प्रश्न पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और वहां के आम नागरिक की जिंदगी का है। महंगाई, रोजगार, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दे किसी भी सरकार के लिए मूलभूत जिम्मेदारियां हैं। विदेश नीति तभी सार्थक होती है जब उसका अंतिम उद्देश्य देश के नागरिकों के जीवन को सुरक्षित, समृद्ध और सम्मानजनक बनाना हो। पाकिस्तान के लिए यह समय इस बात पर गंभीरता से विचार करने का है कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ राजनीतिक और कूटनीतिक अभियान चलाने की तुलना में उसकी जनता की आर्थिक आवश्यकताओं, संस्थागत स्थिरता और मानव विकास पर अधिक ऊर्जा लगाना कितना आवश्यक है।

यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि भारत-पाक संबंधों को केवल आरोप-प्रत्यारोप के चरमे से न देखा जाए। भारत की अपनी सुरक्षा चिंताएं वास्तविक हैं और किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी अपने नागरिकों की सुरक्षा करना है। जयशंकर ने भी संयुक्त राष्ट्र में भारत के आत्मरक्षा के अधिकार और आतंकवाद के

विरुद्ध शून्य-सहिष्णुता की बात कही। लेकिन इसी के साथ क्षेत्रीय शांति के लिए यह भी आवश्यक है कि आतंकवाद के विरुद्ध दृढ़ता और संवाद की संभावनाओं के बीच संतुलन खोजा जाए। संवाद तभी सार्थक हो सकता है जब हिंसा और आतंकवाद के प्रश्न पर स्पष्टता हो। पाकिस्तान को यह भी समझना होगा कि दुनिया आज केवल बयान नहीं सुनती, बल्कि नीतियों और व्यवहार को भी देखती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मूल उद्देश्य ही बहुपक्षीय संवाद, शांति और सहयोग के लिए मंच उपलब्ध कराना है। यदि इस मंच का इस्तेमाल एक-दूसरे के विरुद्ध आरोपों को दोहराने में ही होता रहे, तो दोनों देशों के नागरिकों को उससे क्या हासिल होगा? भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी हैं। इसलिए इनके बीच तनाव केवल द्विपक्षीय समस्या नहीं रहता, उसका प्रभाव पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता पर पड़ सकता है।

आज पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा आत्ममंथन यही होना चाहिए कि वह अपने भविष्य को किस आधार पर निर्मित करना चाहता है-पुराने विवादों, कश्मीर-केंद्रित राजनीति और आतंकवाद के आरोपों के आधार पर या आर्थिक विकास, शिक्षा, रोजगार, संस्थागत मजबूती और क्षेत्रीय सहयोग के आधार पर? भारत के सामने भी चुनौती यही है कि सुरक्षा से समझौता किए बिना दक्षिण एशिया में स्थायी शांति की संभावनाओं को खुला रखा जाए। पाकिस्तान कब बदलेगा, इसका उत्तर कोई दूसरा देश नहीं दे सकता। परिवर्तन अंततः पाकिस्तान की अपनी राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत निर्णयों और नीति-निर्माताओं पर निर्भर करेगा। लेकिन दिशा स्पष्ट है-आतंकवाद को किसी भी रूप में राजनीतिक साधन न बनने देना, अपनी जनता की आर्थिक जरूरतों को प्राथमिकता देना, कश्मीर के नाम पर लगातार टकराव की नीति से आगे बढ़ना और पड़ोसियों के साथ संबंधों को हिंसा के बजाय विश्वास तथा पारस्परिक सम्मान के आधार पर विकसित करना। यदि पाकिस्तान यह रास्ता चुनता है तो उसका लाभ केवल भारत को नहीं, स्वयं पाकिस्तान के नागरिकों और पूरे दक्षिण एशिया को मिलेगा। और यदि वह पुराने रास्ते पर ही चलता रहा, तो सबसे बड़ा प्रश्न दुनिया से अधिक उसके अपने नागरिकों के सामने खड़ा होगा-आखिर कब तक अतीत की राजनीति भविष्य की पीढ़ियों का वर्तमान तय करती रहेगी? (लेखक, पत्रकार, स्तंभकार है)।

राम और शिव के बारे में रेवंत रेड्डी की टिप्पणियां हिंदू धर्म के प्रति उनकी घोर अज्ञानता को प्रदर्शित कर रही हैं

(नीरज कुमार दुबे)

भारतीय राजनीति में धर्म को चुनावी हथियार बनाने की प्रवृत्ति कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब राजनीति सिधे भगवानों के बीच भी वर्ग, क्षेत्र और विचारधारा की दीवार खड़ी करने लगे, तब सवाल सिर्फ किसी एक पार्टी या नेता का नहीं, बल्कि सार्वजनिक जीवन में आस्था की मर्यादा का बन जाता है।

भारतीय राजनीति में भगवानों के नाम पर सियासत कोई नई बात नहीं, लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब सत्ता की राजनीति में भगवानों को भी जाति, वर्ग और क्षेत्र के खाकों में बांटने की कोशिश होने लगे। तेलंगाणा के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के ताजा बयान ने यही सवाल देश के सामने ला खड़ा किया है कि क्या अब भगवान राम और भगवान शिव को भी राजनीति के अलग-अलग खेमों में खड़ा किया जाएगा? क्या राम को अमीरों का और शिव को गरीबों का भगवान बताकर आस्था को भी वोटबैंक की राजनीति में बांटने की कोशिश होगी? सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि एक मुख्यमंत्री के मुंह से निकले ऐसे शब्द देश की धार्मिक और सामाजिक एकता को कहां ले जाएंगे?

हम आपको बता दें कि एक कार्यक्रम में भाजपा पर निशाना साधते हुए तेलंगाणा के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि शिव गरीबों के भगवान हैं, जबकि राम अमीरों के भगवान हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने भगवान राम को चुरा लिया है और उत्तर भारत में चुनावी सफलता के लिए राम की भावना और आस्था का राजनीतिक इस्तेमाल किया। रेड्डी ने अपने तर्क को उत्तर-दक्षिण और द्रविड़-आर्य पहचान से भी जोड़ा। उनका कहना था कि हम द्रविड़ हैं और उत्तर भारत के लोग आर्य हैं। हम शिव के भक्त हैं और वे राम के भक्त हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेता मंचों से हर हर महादेव क्यों नहीं कहते और केवल जय श्रीराम का उद्घोष क्यों सुनाई देता है? रेड्डी ने कहा कि जब दक्षिण भारत में हर हर महादेव बोला जाता है तो भाजपा को यह पसंद नहीं आता।

यहीं से विवाद ने राजनीतिक रूप ले लिया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता बंडी संजय कुमार ने रेड्डी पर भगवान राम और भगवान शिव के बीच राजनीतिक विभाजन खड़ा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाणा के मुख्यमंत्री को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसी तेलंगाणा में वेमुलवाड़ा को दक्षिण काशी और भद्राचलम को दक्षिण

अयोध्या कहा जाता है। ऐसे में राम और शिव को उत्तर और दक्षिण की सीमाओं में बांटना उचित नहीं है। बंडी संजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी और काशी विश्वनाथ से जुड़ाव का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने वेमुलवाड़ा स्थित श्री राजराजेश्वर स्वामी मंदिर का दौरा किया।

देखा जाये तो भारतीय राजनीति में धर्म को चुनावी हथियार बनाने की प्रवृत्ति कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब राजनीति सिधे भगवानों के बीच भी वर्ग, क्षेत्र और विचारधारा की दीवार खड़ी करने लगे, तब सवाल सिर्फ किसी एक पार्टी या नेता का नहीं, बल्कि सार्वजनिक जीवन में आस्था की मर्यादा का बन जाता है। तेलंगाणा के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का ताजा बयान इसी वजह से गंभीर राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। सवाल उठ रहा है कि भगवान राम और भगवान शिव को राजनीति के दो अलग-अलग खेमों में खड़ा करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? क्या किसी भी राजनीतिक दल के लिए यह उचित है कि करोड़ों लोगों की साझा आस्था को अमीर बनाम गरीब या उत्तर बनाम दक्षिण की राजनीतिक श्रेणियों में बांट दिया जाए?

वैसे रेवंत रेड्डी का यह पहला विवादित बयान नहीं है। दिसंबर 2025 में उन्होंने हिंदू देवी-देवताओं की संख्या और अलग-अलग पूजा परंपराओं को लेकर भी ऐसी टिप्पणियां की थीं, जिन पर भाजपा और अन्य विपक्षी दलों ने हिंदू आस्था का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया था। यही वजह है कि अब यह सवाल और तेज हो रहा है कि रेवंत रेड्डी के राजनीतिक भाषणों में हिंदू आस्था ही बार-बार निशाने पर क्यों दिखाई देती है? यहां हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह सवाल उठाना किसी दूसरे धर्म के प्रति पूर्वाग्रह नहीं है; बल्कि उद्देश्य यह पृष्ठना है कि सत्ता और राजनीति में धार्मिक आस्थाओं के साथ समान मर्यादा क्यों नहीं होनी चाहिए?

साथ ही यहां सवाल यह भी उठता है कि धर्म और भगवान पर टिप्पणी कर रहे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को हिंदू धर्म के बारे में कितना ज्ञान है? राम को अमीरों का भगवान बता रहे रेड्डी को शायद यह पता नहीं कि भगवान राम का शरीर ही आश्रम में जाना और उनकी भक्ति स्वीकार करना, निषादराज गुह के साथ उनका आत्मीय संबंध तथा वनवासी समाज के लोगों के साथ उनका लगाव इस बात के उदाहरण हैं कि राम के लिए भक्त की सामाजिक या आर्थिक स्थिति जरा भी महत्व नहीं रखती।

भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी मिलावटखोरी रोकने की व्यवस्था

(उमेश चतुर्वेदी)

महाराष्ट्र की घटनाएं इसलिए सामने आ रही हैं, क्योंकि वहां तेज-तर्रार अधिकारी खाद्य प्रशासन को मिला है। दूसरे इलाकों में ऐसी कार्रवाई नजर नहीं आती। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत में मिलावटखोरी बंद हो गई है। इससे शायद ही किसी को इनकार हो कि शुद्ध खाना और दवा प्राप्त करना हर व्यक्ति का अधिकार है। बिड़बना ही कहेंगे कि जिस मिलावटखोरी से हर साल देश में करीब दो लाख लोग मौत की भेंट चढ़ जाते हैं, फिर भी हमारी कानूनी तंत्र इस पर प्रभावी रोक लगाने में नाकाम रहा है। वैसे तो हर साल ल्योहारी सीजन के साथ ही मिलावटखोरी की चर्चा तेज हो जाती है। लेकिन इन दिनों इस चर्चा की वजह महाराष्ट्र के तेजतर्रार आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे की कार्रवाई है। मुंढे ने जब से महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए के आयुक्त का पद संभाला है, मिलावटखोरों की शامت आ गई है। उन्होंने खाद्य कानूनों और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। महाराष्ट्र एफडीए की टीमों ने शुरूआती 100 दिनों में ही 904 से ज्यादा छापे मारकर 450 से अधिक मिलावटखोरों को गिरफ्तार किया और करोड़ों के मिलावटी खाद्य पदार्थ जप्त किए। इस कार्रवाई से महाराष्ट्र में डिजेंट और रसायनों से बने नकली दूध और ताड़ के तेल से बनने वाले 'एनालॉग पनीर' का रैकेट ध्वस्त हो गया है। नियमों और स्वच्छता मानकों की अनदेखी करने वाले कई नामी फूड चेन्स, बड़े रेस्तराओं आदि के लाइसेंस तक निलंबित या रद्द किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र की घटनाएं इसलिए सामने आ रही हैं, क्योंकि वहां तेज-तर्रार अधिकारी खाद्य प्रशासन को मिला है। दूसरे इलाकों में ऐसी कार्रवाई नजर नहीं आती। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत में मिलावटखोरी बंद हो गई है। इससे शायद ही किसी को इनकार हो कि शुद्ध खाना और दवा



प्राप्त करना हर व्यक्ति का अधिकार है। ब्रिटेन और अमेरिका में ध्यान रखा जाता है कि उपभोक्ताओं तक वही सामान पहुंचे, जो शुद्ध है। ऐसी व्यवस्था भारत में भी की गई है। 2006 में संसद से पारित खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसएआई का गठन किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत कार्यरत इस संस्था का दायित्व खाद्य पदार्थों के मानकों पर निगाह रखना और उन्हें तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना है। राज्यों की पुलिस, प्रशासन और आपूर्ति अधिकारियों को भी अधिकार है कि वे मिलावटखोरी रोकें। ल्योहारी सीजन में ये संस्थाएं कार्रवाइयां करती भी हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, साल 2020 से हर साल करीब एक लाख से अधिक खाद्य नमूनों की जांच की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने पर करीब आठ हजार से ज्यादा खाद्य व्यावसायिक लाइसेंस रद्द भी किए गए हैं। लेकिन देश

में इस पर प्रभावी नियंत्रण नहीं लगाया जा सका है। रोक ना लग पाने के पीछे मोटे तौर पर तीन कारण नजर आते हैं। पहला है, मुनाफाखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति, दूसरा नैतिकता का क्षरण और तीसरा कारण निश्चित तौर पर प्रशासनिक विफलता और भ्रष्टाचार है। विनोबा भावे ने करीब आठ दशक पहले लिखे अपने निबंध 'नवयुवकों से दो बातें' में कहा है कि देश में सुराख ही सुराख हैं। उन्होंने राष्ट्ररूपी घड़े में बने इन सुराखों को सदाचार से भरने की अपील की है। कुछ उसी तरह व्यवस्था में अब भी सुराख हैं। हमारे तंत्र के बड़े हिस्से से सदाचार और कर्तव्यपरायणता गायब है। वह राष्ट्र निर्माण के भाव से दूर है। इस वजह से वक्त पर कार्रवाई नहीं होती। कई बार तंत्र को जानकारी होती है कि फलों कारोबारी आटे में पथर का सफेद बुरादा मिला रहा है, चावलों में प्लास्टिक के दाने फेंट रहा है, दवाओं के सैंपल में गड़बड़ कर रहा है, नकली मावे की मिठाई बेच रहा है, जाली शराब बिक रही है। वक्त पर इन गड़बड़ियों की

जानकारी होने के बावजूद मुनाफाखोर से मिलने वाली चंद रकम के एवज में वह चुप रह जाता है। भले ही नकली दूध पीने से नागरिक बीमार हो रहा हो या नकली शराब से निर्दोष जान जा रही हो। नैतिकता का क्षरण भी मिलावटखोरी के लिए जिम्मेदार है। नैतिकता की कमी मुनाफाखोर कारोबारी और उत्पादक के साथ तंत्र में भी पैठी हुई है। सत्ता संभालते वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने तंत्र को चेताया था कि सब चलता है-वाली मानसिकता की अब गुंजाइश नहीं रही। शुरू में इससे ग्रस्त लोगों में भय दिखा, लेकिन अब तंत्र का बड़ा हिस्सा उसी पुराने ढर्रे पर चलता दिखता है, इसलिए मुनाफाखोरों और मिलावटखोरों का डर कम हो चला है। स्वास्थ्य संविधान के समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए इस मामले में केंद्र के साथ राज्य सरकारों को भी कार्रवाई का अधिकार है। ऐसे में तंत्र को प्रभावी और जवाबदेह बनाने के लिए केंद्र और राज्यों की सरकारों को ज़िरो टालरेंस की नीति अख्तियार करना जरूरी लगता है। तभी मुनाफाखोर, मिलावटखोर और लापरवाह प्रशासनिक तंत्र के पेंच कसे जा सकते हैं। पड़ोसी देश चीन का मिलावटखोरी रोकने वाला 'फूड सेफ्टी लॉ' दुनिया के सबसे कठोर कानूनों में से एक है। जिसके तहत जानबूझकर खाद्य पदार्थों में खतरनाक मिलावट करने वालों को मृत्युदंड देने का प्रावधान है। चीन में साल 2008 में दूध में मेलामाइन रसायन मिलाने के चर्चित मामले के दोषियों को मौत की सजा दी गई थी। स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाली मिलावटखोरों को इस कानून के तहत आज जीवन कारावास के साथ ही भारी आर्थिक जुर्माने का भी प्रावधान है। चीन में खाद्य नियमों का उल्लंघन करने, घटिया या मानकहित उत्पाद बेचने और सबूत नष्ट करने वाली कंपनियों और कारोबारियों पर वहां भारी-भरकम जुर्माना लगाया जाता है। साथ ही व्यवसाय का लाइसेंस रद्द भी किया जाता है।

नानगुर में सेवा सेतु शिविर का आयोजन

बस्तर में अंतिम छोर तक विकास पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता-सांसद श्री महेश कश्यप

बकावंड जनता के गोठ। दशकों तक उपेक्षा और नक्सलवाद का दंश झेलने वाला बस्तर अब बुनियादी सुविधाओं और चौतरफा विकास के नए युग में प्रवेश कर चुका है। नानगुर में आयोजित ब्लॉक स्तरीय विशेष सेवा सेतु शिविर के दौरान क्षेत्रीय सांसद श्री महेश कश्यप ने यह बात कही। कार्यक्रम के दौरान नमो सेवा गाथा का प्रभावी मंचन भी किया गया, जिसमें केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों और सेवा भाव को रेखांकित किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए सांसद श्री कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार का मुख्य ध्येय समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला, जनधन, महतारी वंदन, किसान सम्मान निधि और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के विस्तार पर चर्चा करते हुए बताया कि इन पहलों से ग्रामीणों के



जीवन स्तर में ठोस बदलाव आया है। शिविर के उद्देश्य को रेखांकित करते हुए सांसद ने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक या अन्य तकनीकी विसंगतियों का निवारण मौके पर ही सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने श्रम

विभाग की योजनाओं तथा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सभी पात्र ग्रामीणों का शत-प्रतिशत पंजीयन कराने का आह्वान किया। श्री कश्यप ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए समर्पित जनसेवा ही सबसे सशक्त माध्यम है।



शिविर में प्राप्त कुल 235 आवेदनों पत्रों का मौके पर निराकरण किया गया। इस दौरान शासन की विभिन्न जनहितकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। जिसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत लाभान्वित चार हितग्राहियों को उनके नवीन आवासों की चाबी सौंपी

गई। वहीं कृषि विभाग द्वारा 10 किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तरीय टैलेंट तिहार में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दो बच्चों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उसावर्धन किया गया। साथ ही मुस्कुराता बस्तर स्पर्धा के



तीन बच्चों को पांच-पांच हजार रूपए की सम्मान निधि से पुरस्कृत किया गया। राजस्व विभाग द्वारा पांच किसानों को भू अधिकार अभिलेख तथा पांच किसानों को खसरा-बीवन नकल प्रदाय किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चार हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड वितरित

किया गया। इस मौके पर क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों सहित एसडीएम श्री मनीष वर्मा, उप संचालक पंचायत श्री बिरेंद्र बहादुर के अलावा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन मौजूद थे।

रेशम से खुलेगी समृद्धि की राह

बस्तर में टसर कीट पालन और धागाकरण को बढ़ावा, बांटे गए प्रोत्साहन चेक

टसर रेशम कीट पालन एवं रेशम धागाकरण प्रशिक्षण सह अलंकरण समारोह का आयोजन



तथा संस्थाओं के प्रतिनिधियों से सीधा संवाद कर उनके मैदानी अनुभवों और आजीविका गतिविधियों की विस्तृत जानकारी ली। इसके साथ ही रेशम उत्पादन को प्रोत्साहित करने और हितग्राहियों का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से उन्होंने संबंधित समूहों एवं संस्थाओं को प्रोत्साहन चेक प्रदान किए। चेक वितरण के उपरांत उन्होंने रेशम धागाकरण इकाई का सघन अवलोकन करते हुए कोकून से धागा तैयार करने की संपूर्ण तकनीकी कार्यप्रणाली का जायजा लिया और महिला कामगारों के कोशल की सराहना की। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए जिला पंचायत

अध्यक्ष श्रीमती कश्यप ने कहा कि बस्तर की उर्वरा मिट्टी और वनांचल में रोजगार तथा आत्मनिर्भरता की अपार संभावनाएं समाहित हैं। उन्होंने कहा कि टसर रेशम से जुड़े ग्रामीणों और स्व-सहायता समूहों को आधुनिक प्रशिक्षण, आवश्यक तकनीकी संसाधन और वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराकर स्थानीय स्तर पर आजीविका के अवसरों को सुदृढ़ बनाना प्रशासन की सर्वाच्च प्राथमिकता है। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री बलदेव मंडवी, उप संचालक (रेशम) श्री रोशन चंद्राकर, स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित अधिकारिगण उपस्थित रहे।

साइबर जागृति अभियान: साइबर अपराध से बचाव के प्रति किया जागरूक

कोरबा। साइबर जागृति अभियान के तहत नगर निगम कोरबा के सभागृह में बुधवार को 'साइबर चेपाल' का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों और आमजन को साइबर अपराध से बचाव तथा सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन रहे। इस अवसर पर महापौर संजू देवी राजपूत, कलेक्टर कुणाल दुदावत, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन, नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडे, भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, छात्र-छात्राई और आमजन मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने ओटीपी फ्रॉड, अनजान लिंक, फर्जी िच्छ, फ्त कोड, डिजिटल अफेयर्स और ऑनलाइन ठगी से बचाव के उपाय बताए। उन्होंने ओटीपी और गोपनीय जानकारी

किसी से साझा नहीं करने तथा सदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करने की अपील की। कलेक्टर कुणाल दुदावत और जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन ने ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर जागरूकता बढ़ाने और डिजिटल सुविधाओं का सावधानीपूर्वक उपयोग करने पर जोर दिया। मंत्री लखन लाल देवांगन ने उपस्थित लोगों को साइबर सुरक्षा की शपथ दिलाई। कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए 'मैं साइबर जागरूक हूँ' सेल्फी बोर्ड के माध्यम से भी साइबर सुरक्षा का संदेश दिया गया। कोरबा पुलिस द्वारा 15 अगस्त से साइबर जागृति अभियान के तहत जिलेभर में स्कूल-कॉलेज, बाजार, ग्राम पंचायतों और सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पुलिस ने साइबर ठगी होने पर तत्काल 1930 पर संपर्क करने तथा बलइमतब तपसु.हवअ.पद पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की।

वनांचल में पुलिस-ग्रामीण संवाद बढ़ाने एसपी की पहल, जमीन पर बैठकर सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं

कबीरधाम। वनांचल क्षेत्र में पुलिस और ग्रामीणों के बीच बेहतर समन्वय और विश्वास मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव ग्राम कनहरी पहुंचे। यहां आयोजित संस्थाकालीन जनचौपाल में एसपी ने ग्रामीणों के बीच जमीन पर बैठकर उनकी समस्याएं सुनीं और क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीधे संवाद किया। जनचौपाल में तीन पंचायतों के सरपंचों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जनचौपाल के दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के साथ पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा से संबंधित शिकायतें पुलिस अधीक्षक के सामने रखीं। एसपी जितेन्द्र कुमार यादव ने ग्रामीणों की बात गंभीरता से सुनी और संबंधित मामलों में आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस और आमजन के बीच निरंतर संवाद रहने से



समस्याओं का समय पर समाधान करने के साथ-साथ अपराधों की रोकथाम में भी मदद मिलती है। पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीणों से अपील की कि गांव या आसपास के क्षेत्र में किसी भी तरह की सदिग्ध गतिविधि, अवैध कार्य या सदिग्ध व्यक्ति नजर आने पर इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। उन्होंने नशे के खिलाफ जागरूक रहने और युवाओं को नशे से दूर रखने के साथ निरंतर संपर्क बनाकर अपराध की रोकथाम के लिए प्रभावी वातावरण तैयार करना भी है। उन्होंने ग्रामीणों से पुलिस का सहयोग करने और क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में सहभागी बनने की अपील की।

उपायों की जानकारी दी गई। पुलिस ने अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने, ओटीपी और बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करने तथा ऑनलाइन ठगी होने पर तत्काल समस्याओं का सूचना देने की अपील की। इसके अलावा महिला सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति भी ग्रामीणों को जागरूक किया गया। एसपी ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करना नहीं, बल्कि ग्रामीणों के साथ निरंतर संपर्क बनाकर अपराध की रोकथाम के लिए प्रभावी वातावरण तैयार करना भी है। उन्होंने ग्रामीणों से पुलिस का सहयोग करने और क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में सहभागी बनने की अपील की।

नशे के खिलाफ पुरन्दर मिश्रा की 28 साल की मुहिम, गांधी जयंती पर राज्यपाल रमेन डेका हुए शामिल

राज्यपाल रमेन डेका ने की पदयात्रा, गांधी-शास्त्री-अंबेडकर की प्रतिमाओं पर अर्पित किए श्रद्धासुमन

रायपुर जनता के गोठ । सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री पुरन्दर मिश्रा के नेतृत्व में पिछले 28 वर्षों से निरंतर चलाए जा रहे नशामुक्ति जनजागरण अभियान का गांधी जयंती के अवसर पर समापन हुआ। 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित साप्ताहिक नशामुक्ति जनजागरण पदयात्रा के समापन अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमेन डेका जी, कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब जी, रायपुर सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कल्याण मंडल के अध्यक्ष श्री रामप्रताप सिंह जी, रायपुर शहर जिला अध्यक्ष श्री रमेश ठाकुर जी , रायपुर दक्षिण विधायक श्री सुनील सोनी जी, रायपुर महापौर श्रीमती मीनल चौबे जी सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए।

28 वर्षों से निरंतर जारी है नशामुक्ति जनजागरण अभियान विधायक श्री पुरन्दर मिश्रा द्वारा नशे के खिलाफ जनजागरण की यह मुहिम पिछले 28 वर्षों से निरंतर जारी है। इस अभियान के माध्यम से

समाज को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने, युवाओं को नशे से दूर रखने तथा स्वस्थ, संस्कारवान एवं सशक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया जा रहा है। 25 सितंबर से शुरू हुई साप्ताहिक नशामुक्ति जनजागरण पदयात्रा रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरी। इस दौरान बड़ी संख्या में नागरिकों, युवाओं एवं कार्यकर्ताओं ने सहभागिता करते हुए नशामुक्त समाज के संकल्प को मजबूत किया।

गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई शुरुआत समापन कार्यक्रम की शुरुआत कलेक्टर परिसर स्थित टाउन हॉल से हुई। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके पश्चात नशामुक्त समाज के संकल्प और जनजागरण के संदेश के साथ पदयात्रा प्रारंभ हुई। शास्त्री चौक में अर्पित किए श्रद्धासुमन पदयात्रा टाउन हॉल से शास्त्री चौक पहुंची, जहां राज्यपाल श्री



रमेन डेका सहित उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। अंबेडकर चौक में डॉ. अंबेडकर को किया नमन इसके बाद पदयात्रा अंबेडकर चौक पहुंची, जहां भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सामाजिक न्याय, समानता और जनकल्याण के उनके विचारों को

नमन किया गया। नशामुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में जनजागरण इस अवसर पर विधायक श्री पुरन्दर मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की नशामुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने और छत्तीसगढ़ को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से जनजागरण अभियान को निरंतर व्यापक स्वरूप दिया जा रहा है। नशे के दुष्प्रभावों के प्रति समाज के प्रत्येक वर्ग को जागरूक



करना, युवाओं को नशे से दूर रखना और उन्हें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाना इस अभियान के

प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि नशे का प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं

रहता, बल्कि इसका असर पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है। पिछले 28 वर्षों से नशामुक्ति के प्रति जनजागरूकता का यह अभियान युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने और स्वस्थ, संस्कारवान एवं सशक्त समाज के निर्माण के उद्देश्य से निरंतर आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि नशामुक्ति केवल एक आयोजन तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि यह निरंतर जनभागीदारी और सामाजिक जागरूकता का विषय है। सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग को नशामुक्ति के संकल्प से जोड़ने और युवाओं को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास लगातार जारी रहेगा। कार्यकर्ताओं एवं सहयोगियों का सम्मान समापन समारोह में अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं एवं सहयोगियों को पुष्पगुच्छ एवं स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया। नशामुक्ति के लिए जनजागरण में योगदान देने वाले लोगों के प्रयासों की सराहना की गई। गांधी जयंती पर आयोजित इस

पदयात्रा ने नशामुक्त समाज के निर्माण, सामाजिक जागरूकता और जनभागीदारी का संदेश दिया। इसके साथ ही 25 सितंबर से शुरू हुई साप्ताहिक नशामुक्ति जनजागरण पदयात्रा का विधिवत समापन हुआ। प्रमुख रूप से उपस्थित रहे लौह शिल्पकार विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रफुल्ल विश्वकर्मा, श्रम कल्याण मंडल के उपाध्यक्ष श्री किशोर महानंद, हज्र कमेटेटी के अध्यक्ष श्री मिर्जा एजाज बेग, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री राजीव लोचन महाराज, प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट श्री पीयूष मिश्रा, सभापति श्री सूर्यकांत राठौर, जिला उपाध्यक्ष श्री अकबर अली, भाजयुमो जिलाध्यक्ष श्री अर्पित सूर्यवंशी, अजा मोर्चा जिलाध्यक्ष श्री पंकज जगत, जिला मंत्री श्रीमती अर्चना हुकरे, जिला सह-कार्यालय मंत्री श्री अनूप खेलकर, मंडल अध्यक्ष श्री राम प्रजापति सहित अन्य जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, अधिकारी-कर्मचारीगण तथा बड़ी संख्या में नागरिक एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे।

ग्रामीण अंचल के तीन शिक्षकों को मिला राज्य स्तरीय 'एजुकेशन स्कल्पटर अवार्ड 2026'

बकावंड जनता के गोठ। ग्रामीण अंचलों में सीमित संसाधनों के बीच नवाचार के जरिए शिक्षा को बेहतर बनाने वाले छत्तीसगढ़ के उत्कृष्ट शिक्षकों को राज्य स्तरीय 'एजुकेशन स्कल्पटर अवार्ड 2026' से सम्मानित किया गया। एमडी एजुकेशन सोसाइटी सरायपाली एवं 'शिक्षा सारांश' शैक्षिक मासिक पत्रिका के संयुक्त तत्वावधान में तथा कलिंगा यूनिवर्सिटी रायपुर के सहयोग से आयोजित एक दिवसीय शैक्षिक संगोष्ठी सह शिक्षाविद शिल्पी सम्मान समारोह में यह सम्मान प्रदान किया गया। समारोह में छत्तीसगढ़ शासन के राज्य शिक्षा आयोग के अध्यक्ष एवं राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त सुधीर गौतम, कलिंगा यूनिवर्सिटी के कुलसचिव संदीप गांधी, भूमि बिल्डकॉन एंड डेवलपर्स रायपुर के प्रतिनिधि प्रमोद डेहरी एवं डॉ. अनिल कुमार प्रधान ने



शिक्षकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर शासकीय प्राथमिक शाला ढाबामारी के सहायक शिक्षक नोगेश कुमार साहू को TLM, खेल-खेल में सीखने, FLN, पालक-शिक्षक संवाद और बाल-मित्रवत वातावरण विकसित करने के लिए सम्मान मिला। उनके प्रयासों से बच्चों की उपस्थिति तथा विभिन्न गतिविधियों में सहभागिता बढ़ी है। वहीं शासकीय प्राथमिक शाला दोदरगुड़ा के सहायक शिक्षक पीयूष कुमार पाल को ग्रामीण समुदाय से बेहतर समन्वय, बच्चों की दर्ज संख्या बढ़ाने, गतिविधि

आधारित शिक्षण तथा स्रष्टृ के क्षेत्र में DRG एवं BRG के रूप में शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के योगदान के लिए सम्मानित किया गया। शासकीय प्राथमिक शाला लिमऊपदर बिन्ता के सहायक शिक्षक श्याम सिंह नुट्टी को अंग्रेजी विषय में गतिविधि आधारित शिक्षण, TLM के उपयोग तथा खेलकूद, चित्रकला और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सम्मान मिला। आयोजन समिति ने शिक्षकों के नवाचार, समर्पण और ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद ऐसे शिक्षक अपनी रचनात्मक पहल से बच्चों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

